प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

17.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार गग्गल एयरपोर्ट और गगरेट में ज़मीन के बेनामी सौदों की जांच करवाएगी। उन्होंने इसके लिए पुलिस की एस.आई.टी के गठन की घोषणा की। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने गगरेट के विधायक राकेश कालिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों स्थानों पर हुई ज़मीन की बेनामी खरीद और उसमें कथित दलाली दिए जाने के मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पैसे का बेनामी लेन–देन किया है, तो उसकी ज़मीन ज़ब्त होगी और उसे मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जांच में ऐसा कोइ मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के तहत अभी तक 4 हज़ार 6 सौ 49 लोगों को एक हज़ार 4 सौ 60 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये राशि भू–अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावितों के खाते में ट्रांसफर की गई है।

नरेश बंसल

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे, विमानन और जल परिवहन में बड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़े और आर्थिक विकास को गति मिले। नरेश बंसल ने बजट को "शानदार और आमजन हितैषी" बताया। उन्होंने कहा कि 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आर्थिक विकास और नियंत्रित महंगाई को सुनिश्चित किया है। नरेश बंसल ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। डॉ. बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला है।

प्रदर्शन

प्रदेश पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज शिमला के चौड़ा मैदान में धरना–प्रदर्शन किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा पैंशनरों की मांगों को बार–बार अनेदखा किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार

पैंशनरों और कर्मचारियों की विरोधी बन गई है। सुरेश ठाकुर ने कहा कि राजस्व अनुदान घाटे के बंद होने का पैंशनरों की पैंशन और कर्मचारियों के वेतन व बकाया राशि से कोई लेना–देना नहीं है। पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया।

भारत विस्तार

केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जयपुर से किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी भारत विस्तार का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को स्मार्ट, सशक्त और सूचना–समृद्ध बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फोन से एक ही कॉल में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें न केवल कृषि से बल्कि पशुपालन से भी जोड़ना आवश्यक है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

.....